International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –0.899
Vol.6 No.3 Jan–Feb 2019

बढ़ती जनसंख्या एवं बेरोजगारी

डॉ. कल्पना निरंजन
एसोसिएट प्रॉफेसर (अर्थशास्त्र विभाग)
आर्यकन्या डिग्री कॉलेज, झाँसी

वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में हम अगले कुछ वर्षों में चांद पर कदम रखने का सपना भले ही सच कर लें, लेकिन दिन-दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए हमारे पास कोई रामबाण नुस्खा नहीं है। किसी भी देश के पास आबादी की जरूरतें पूरी करने की एक सीमा होती है, भारत यह सीमा बहुत पहले ही पार का चुका है, इस दिशा में चल रहे सभी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान नाकाफी रहे हैं, आजादी के उपरांत विगत ६३ वर्षों में भारत ने विकास की अनेक मंजिलें सफलतापूर्वक तय की हैं, अनेक क्षेत्रों में देश आत्मनिर्भर भी होता जा रहा है, परन्तु तेज गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि से न केवल हमारे राष्ट्र बल्कि वरन् विश्व के अन्य देशों के विकास कार्यों का समुचित लाभ आम आदमी तक न पहुंचने का एक प्रमुख कारण अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ही है, जनसंख्या विस्फोट इस शताब्दी की सबसे बढ़ी समस्या है, विश्व के सभी विकसित, विकासशील देश के लिए यह समस्या अधिक गम्भीर है, वर्तमान समय में विश्व की लगभग १६.७ प्रतिशत जनसंख्या भारत में रह रही है, जबकि भारत का विस्तार केवल २.४ प्रतिशत भू-भाग में ही है। भारत का क्षेत्रफल अमेरिका के एक तिहाई क्षेत्रफल में बराबर है, लेकिन भारत की कुल जनंसख्या अमेरिका से तीन गुना ज्यादा है। जनसंख्या विशेषज्ञों के अनुसार देश में प्रतिवर्ष जनसंख्या की दृष्टि से एक आस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है।

अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि की यह समस्या देश की प्रगति और सम्पन्नता में चीन की दीवार की तरह अवरोध बनकर हमारे सामने खड़ी है। वर्ष २०११ में देश की संख्या १०२ करोड़ ७० लाख थी, हर वर्ष इसमें १ करोड़ ८० लाख नये व्यक्ति जुड़ते रहे हैं। अनुमानों के आधार पर इस वक्त भारत की आबादी १. २२ करोड़ आंकी गयी है। वर्ष २०११ की जनगणना, का कार्य चल रहा है। नतीजे निश्चित ही चौकाने वाले होंगे, वर्तमान गति से २०५० में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़कर एक अरब तिरेपन करोड (१.५३ करोड़) हो जायेगी। प्रत्येक वर्ष विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का पांचवा भाग अकेले भारत में ही बढ़ जाता है। देश में जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक स्थिति में पहुंच गयी है। देश में प्रति दो सेकेण्ड में ३ बच्चे एवं एक वर्ष में लगभग दो करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। इस अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारी विकास योजनायें लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाती है। जनसंख्या विस्फोट वास्तव में शांति, प्रगति एवं सम्पन्नता के मार्ग में दुष्कर अवरोध है।

विकासदर में वृद्धि के बावजूद देश का आम आदमी आज भी अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जूझ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। भारत का विकास अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को सहन नहीं कर पा रहा है। जनसंख्या की बेलगाम रफ्तार से जनसंख्या घनत्व भी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। २००१ में भारत का जनसंख्या घनत्व ३२४ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था जो कि २०११ में ३८१ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. होने के संकेत मिल रहे है। यही गति रही तो वर्ष २०२५ में जनघनत्व बढ़कर ४४० व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. हो जायेगा। नि:संदेह तीव्र जनसंख्या वृद्धि से भूमि पर दबाव बढ़ता है और संसाधनों का बहुत अधिक दोहन होता है। वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में भोजन, आवास, पानी, रोशनी पर्यावरण का बहुत कुठाराघात किया है। २००१ की जनगणना के अनुसार देश में १७.९ करोड़ मकान थे, प्रत्येक भारतीय को छत नसीब हो सके, इसके लिए ५.५ करोड़ मकानों की अनिवार्य आवश्यकता है। आवास के अभाव में लाखों लोग झोपड़-पट्टियों तंग गलियों में सीलनसुक्त अनुपयुक्त मकानों में रहने को विवश होते हैं।

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि में आम आदमी ने स्वच्छ व पर्याप्त जल को बहुत दूर कर दिया है। आंकड़े बतलाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र २५ प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में ६५ प्रतिशत लोगों को ही पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। अनेक राज्यों में तो स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक परिवारों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। पैसे खर्च करने के लिए तैयार होने के बाद भी लोग बिजली, ईंधन जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बढ़ती आबादी के सामने हमारे संसाधन कम पड़ गये हैं। देश में आज भी ४४ प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है। देश में अभी भी मांग की तुलना में १००००० मेगावाट बिजली का उत्पादन कम है। स्वाभाविक है कि आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रोशनी से वंचित होकर अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दरके कारण गांव से लेकर शहरों तक चिकित्सीय सुविधायें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ३ वर्ष से कम उम्र के ४६ प्रतिशत बच्चे पोष्टिक आहार के अभाव का शिकार हैं। देश की १५-४९ वर्ष की ५६.२ प्रतिशत विवाहित महिलायें खून की कमी से ग्रस्त हैं। विश्व की जनसंख्या के १६.५ प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं, लेकिन विश्व की बीमारियों में भारतवासियों का योगदान लगभग २० प्रतिशत है। विभिन्न बीमारियों के साथ-साथ प्रसव पूर्व और प्रसव बाद रोगों से ग्रसत महिलाओं में से एक तिहाई महिलायें भारत में ही रहती हैं, देश की बढ़ती आबादी अपनी आवश्यकता के लिये जंगलों और वनों को काट रही है। जंगलों के कटने से लगभग एक प्रतिशत क्षेत्रफल हर वर्ष रेगिस्तान में बदल रहा है। अपनी जरूरतों के लिए अंधाधुंध लकड़ी काटने से मिट्टी में नमी कम हो रही है और भूजल स्वर तेजी से गिर रहा है। बढ़ती आबादी में पर्यावरण को इस सीमा तक प्रभावित किया है कि हर वर्ष लगभग १०० जिले जहाँ सूखे का प्रकोप झेलते हैं वहीं करीब ८० जिलों की ४ करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ में डूबती हैं।

हमारे देश में जनसंख्या के आकार, प्रकृति, वृद्धि दर एवं जैविकीय तथा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर विषमतायें दिखलाई पड़ती हैं। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से हमारे देश का विश्व में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि में सातवां स्थान है। पिछ्ले १०० वर्षों में देश की जनसंख्या चौगुनी से भी अधिक हो गयी है। वर्तमान समय में देश की कुल आबादी अमेरिका और रूप की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। आज हालत यह है कि विश्व के प्रत्येक ६ व्यक्ति में से एक भारतीय है। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण ही देश में १.८ करोड़ लोग प्रतिवर्ष जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। जो ब्राजील की कुल जनंसख्या से भी अधिक है। जनसंख्या की यह वृद्धि रोजगार, कीमतों, उपभोग के स्तर, आय, शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा, आवास, प्रशासन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर हम जनसंख्या के वितरण को देश में विभिन्न राज्यें की दृष्टि से देखें तो ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू जैसे राज्यों में जनसंख्या की बहुलता है। जबकि त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, असम, हरियाणा, गुजरात, हिमांचल प्रदेश जैसे राज्यों की जनसंख्या कम है। १९८१-९१ में देश की जनसंख्या वृद्धि दर जहाँ २३.८ प्रतिशत थी, वही १९९१-२००१ में यह २१.३ प्रतिशत रही। देश में दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक ४६.३ प्रतिशत रही है। देश की कुल जनसंख्या का आधा भाग उ०प्र०, बिहार, महाराष्ट्र पं० बंगाल, राजस्थान में ही निवास करता है।

"जीम चतपदबपचंस व िछंजनतंस पदबतमेंम पद जीम चवचनसंजपवद" एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से समाजशास्त्री, कमउवहतंचीमते और योजना आयोग ूलिकर किसी भी समाज और स्थान के भविष्य का आंकलन करते हैं और तरह-तरह की योजनाये बनाते हैं ताकि उन इलाकों का विकास हो। चतपबपचंस व िदंजनतंस पदबतमेंम पद चवचनसंजपवद जनसंख्या बृद्धि को बड़े ही तार्किक रूप में परिभाषित करता है मानता है किसी भी इलाके में समय के साथ जनसंख्या वृद्धि होगी ही इसे टाला नहीं जा सकता। भारत सरकार द्वारा अस्सी के दशक में दिया गया नारा " हम दो हमारे दो" भी चतपबपचंस व िदंजनतंस पदबतमेंम पद चवचनसंजपवद के एक आदर्श scenrio को ही परिलक्षियत करता है। ये नारा सन्देश देता है कि आबादी बढ़ना आवश्यक है, मगर हम नेचुरल इन्क्रीम इन पॉपुलेशल के सिद्धांतों की अनदेखी करेंगे तो जनसंख्या विस्फोट का खतरा पैदा हो सकता है।

क्या भारत में हो रही जनसंख्या वृद्धि को नेचुरल इनक्रीस इन पॉपुलेशन माना जा सकता है या फिर ये इशारा करता है जनसंख्या विस्फोट की ओर? इन प्रश्न का जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के अनुपास में जो रोजगार के अवसर अपलब्ध करवाए जा रहे वो काफी नहीं हैं। जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि का सिद्धांत अपने आसपास एक फ्रेमवर्क बुनता है, इस फ्रेमवर्क में सबसे पहले स्टडी किया जाता है इलाके के प्राकृतिक संसाधनों को, उदाहरण के तौर पर हम चेन्नेई का उदाहरण ले सकते हैं। हाल में प्रकाशित खबरों के अनुसार चेन्नई में भूमिगत जल का स्तर १००० फीट से नीचे पहुँच चुका है, इस शहर पर जिस लरह से आबादी का बोझ बढ़ रहा है, आने वाले समय में यहाँ जल संसाधन की भारी किल्लत होने की संभावना है। इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जा सकता है। पहले शहर की आबादी बढ़ी उसके बाद शहर का ईको सिस्टम व्यस्त हुआ और आखिर में वो स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसकी वजह से कास्ट ऑफ लिविंग में पानी की बेतहाशा बढ़ती कीमत भी दर्ज हो गयी। जिस तरह मुंबई में बसे लोग रियल एस्टेट के किरायो से नाखुश है उसी तरह पूरी सम्भावना है की आने वाले समय में चेन्नई का वाटर टैक्स यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाए।

मगर चेन्नई शरह की इसी बढ़ती हुयी आबादी का बोझ शहर के रोजगार इंडेक्स पर नहीं पड़ेगा। जैसे-जैसे आबादी का घनत्व बढ़ेगा उसी अनुपास में सर्विस इकॉनामी की आवश्यकता भी बढ़गी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। तथ्यात्मक रूप से कहा जा सकता है कि बढ़ती हुयी आबादी का घटते हुए रोजगार के अवसरों से कोई लेना देना नहीं है। इसे समझने के लिए हम माइग्रेशन के ट्रेंड्स भी देख सकते हैं।

पिछले कई वर्षों के डेमोग्राफिक आंकड़े गांवों से शहरों की ओर पलायन की तस्वीय दिखाते हैं। सत्तर और अस्सी के दशक में पलायन इसलिए हुआ क्योंकि महानगरों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा था और रोजगार के अवसर भी ज्यादा थे। वहां पर हर वस्तु की खपत ज्यादा थी और इसी वजह से महानगर आर्थिक गतिविधि का केंद्र भी बन गए थे।

नब्बे के दशक में गांवों और छोटे शहरों की आबादी भी बढ़ी। सन् १९९१ में आये अर्थव्यवस्था सुधारों के बाद तो बड़े बड़े उद्योगों ने छोटे शहरों और गांवों का रूख किया। यहाँ पर रोजगार सृजन भी हुआ मगर इसके बाद भी गाँवों से बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं रूका। इस दौर में पलायन का कारण था गांव में नौकरी और श्रम का उचित मेहनताना नहीं मिलना। हम ये भी कह सकते हैं कि नब्बे और दो हजार के दशक में पलायन इसलिए भी हुआ क्योंकि युवाओं को लगा की वो छोटे शहरों और गाँवों में न्दकमत.म्उचसवलमक ही रह जायेंगे।

२१वीं सदी में हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ हम पाते हैं कि बड़े शहर अपनी क्षमताओं का पूरा विस्तार कर चुके हैं और बंततलपदह बंचंबपजल से ज्यादा आबादी होने की वजह से हांफ रहे हैं या फिर चेन्नई की तरह टूटने की कगार पर हैं। मध्ययम स्तर के शहर अब भी स्तर पर रोजगार उपलब्ध तो करवा रहे हैं मगर बढ़ती हुयी महंगाई के अनुपात में आय काफी कम है। इस दौर में आश्चर्यजनक रूप से गांवों में रोजगार में वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण है जीवन यावन की लागत कम होना और उसी अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना।

क्या अब भी हम कह सकते हैं कि रोजगार की कमी के पीछे बढती हुयी आबादी का हाथ है। यहाँ पर अथव्यवस्था के स्वरूप को समझना भी आवश्यक हो जाता है। अस्सी के दशक में अर्थव्यवस्था के सुअवसर तकनीक के पास थे, इस दौर में कारखाने स्थायी रोजगार देने में सक्षम थे। बड़े कारखानों में बड़े पैमानों पर वस्तुओं का उत्पादन होता था। मुनाफे का अर्थ होताथा अपनी उंदनबिजनतपदह क्षमता का सतत् विस्तार।

फिर आया नब्बे का दौर, ये आई टी का दौर था जब कप्यूटर और बाकी तकनीको ने बिजनस मॉडल्स को दोबारा स्थापित किया और नए उद्योग धंधे, बिजनेस / थॉट जैसी परिकल्पनाए के आधार पर चलने लगे। डें चतवकनबजपवद की जगह ले ली ''मंपिबपमदज पदअमदजवतल'' ने। ज्ञान आधारित इकॉनमी या नोलेज

इकॉनमी का दौर आ गया। २१वीं सदी में प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी जुड़ गयी, इस प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की वजह से एक स्तर पर नौकरी कम हुयी जहाँ उत्पादों को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का सहारा लिया जाता था। वहीं पर सर्विस ओरिएंटेशन की वजह से नए रोजगार का सृजन भी हुआ (मिश्र, २०२०)। यदि इस लिहाज से देखा जाए तो आबादी कहीं से भी वो पैमाना बन कर नहीं उभरती जो बेरोजगारी को जन्म दे। सत्य तो ये है कि हमेशा से ही रोजगार सृजन घनी आबादी के क्षेत्रों में ही हुआ है। या फिर जैसे ही रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, कोई भी क्षेत्र सघन आबादी वाले क्षेत्र में तब्दील हो गया है।

बेरोजगारी को समझने के लिए सफलता और असफलता का अनुमान लगाने के लिए आमतौर पर किसी भी देश, प्रान्त या जिले में कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या देखी जाती है। कामकाजी उम्र यानी १८ से ५९ वर्ष तक के लोग। जनसंख्या के सैंपल में इस आयुवर्ग के कितने लोग बेरोजगार हैं इस आधार पर किसी भी स्थान का एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स निकाला जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

१. चौहान, बी०एस० गौतम, एम० - 'भारत' रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ २००५-२००६
२. उत्तर प्रदेश ज्योग्राफिकल जर्नल्स, वाल्यूम ८, २००३, पेज ५५
३. दैनिक जागरण, कानपुर, १ जनवरी, २००८
४. दैनिक जागरण, कानपुर, ५ सितम्बर, २००९